MR. CHAIRMAN: Now, Question No. 143—Shri Lekhraj Bachani.

श्री संघ प्रिय गौतम: सभापति जी। नियम की बात है। ...(व्यवधान)... मेरा नियम का सवाल है। मेरा एक सवाल पाइंट आफ आर्डर का है। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: प्रश्नकाल में पाइंट आफ आर्डर नहीं होता है। ...(व्यवधान)...

श्री टी॰ एन॰ चतुर्वेदी: सभापति महोदय, अगर प्रश्नकर्ता प्रश्न नहीं पूछता है तो हमें प्रश्न पूछने की अनुमति मिलनी चाहिए। ...(व्यवधान)...

*143. [The questioner (Shri Bachani Lekhraj) was absent. For answer *vide* page 23 *infra*.]

MR. CHAIRMAN: Question No. 144—Shri Rajnath Singh 'Surya'.

Journals on defence and strategic studies in Hindi

†*144. SHRI RAJNATH SINGH 'SURYA': Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is dearth of magazines and journals in Hindi language in the field of defence and strategic studies;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether Government are implementing any scheme to provide information in Hindi with respect to matters related to defence;

(d) if so, the details thereof; and

(e) if not, whether Government have any proposal in this regard?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) and (b) Magazines/Journals/Articles in the field of Defence and strategic studies are being published from time to time . The frequency of these publications would largely depend on the perceived demand of the target Hindi readers.

(c) to (e) Yes, Sir. Cash award schemes are being implemented to encourage Hindi publications of Defence related matters. There is a Biannual cash award scheme ranging from Rs. 2000 to Rs. 15000 as well as an Annual cash award scheme for 'in-house' Hindi publications.

†Original notice of the question was received in Hindi.

श्री राजनाथ सिंह "सूर्य": सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह कहा है कि हिन्दी की पत्रिकाएं मांग का ध्यान रखते हुए समय-समय पर प्रकाशित की जाती हैं। इसका मतलब यह लगाया जाए कि इनके नियमित का कोई प्रावधान नहीं है, कोई मापदंड नहीं है कि ऐसी पत्रिकाएं नियमित प्रकाशित की जाएं। जहां तक मैं समझता हूं, अंग्रजी में रक्षा विभाग की पत्रिकाएं नियमित रूप से प्रकाशित की जाती हैं तो नियमित रूप से उसी प्रकार से इसका हिन्दी में प्रकाशन क्यों नहीं होता, यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज: सभापति महोदय, रक्षा मंत्रालय की ओर से कोई भी पत्र-पत्रिका प्रकाशित नहीं होती है। जिन पत्र-पत्रिकाओं की बात मैंने यहां पर की, वह तो जो सामान्य पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं, जैसे हमारे प्रोडक्शन सेंटर्स या अन्य कोई यूनिट हैं, जो अपनी तरफ से उनको प्रकाशित करते हैं, उसके बारे में मैंने यहां पर कहा। मंत्रालय की ओर से कोई भी पत्र या पत्रिका प्रकाशित नहीं होती है।

श्री राजनाथ सिंह "सूर्य": श्रीमन्, यह बड़े आश्चर्य की बात है कि मंत्री जी ने कहा कि रक्षा मंत्रालय के संदर्भ में जानकारी देने के लिए मंत्रालय की ओर से कोई पत्रिका प्रकाशित नहीं होती है। मंत्रालय की तरफ से नहीं होती होगी लेकिन नौसेना, वायुसेना और थलसेना की ओर से उनकी गतिविधियों के बारे में जानकारी देने के लिए कुछ पत्र-पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं और कभी-कभी वे पत्रिकाएं हमारे पास भी आती हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि उनका स्वरूप नियमित नहीं है और आज जिस प्रकार के खुलेपन की स्थिति है, उसमें रक्षा के मामले में बहुत सी जो सामान्य जानकारियां हैं, वह आम नागरिक जानना चाहता है। तो क्या इस पर मंत्री जी विचार करेंगे क्योंकि रक्षा के संबंध में जो आज्ञाएं दी जाती हैं, बाकी सब कुछ होता है, वह हिन्दी में होता है लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि रक्षा विभाग के जो विद्यालय हैं, उनमें केवल अंग्रेजी में पढ़ाई होती है। इसके संबंध में कई बार चर्चा हुई की कि कम से कम हिन्दी में भी उनमें पढ़ाई की जाए लेकिन आज तक उस पर निर्णय नहीं लिया जा सका। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि क्या वे इस पर विचार करेंगे कि हिन्दी की पत्र-पत्रिकाएं नियमित रूप से प्रकाशित की जाएं और रक्षा संबंधी जो जानकारी सामान्य लोगों को देने की आवश्यकता है या विभाग के अंतर्गत ही जो सूचनाएं आदान-प्रदान करने की आवश्यकता है, उसको ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की पत्रिकाएं प्रकाशित की जाएं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज: महोदय, इस पर विचार करके हम किसी निर्णय पर पहुंचेंगे।

श्रीमती गुरचरण कौर: सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगी कि स्वतंत्रता के पचास वर्ष बाद भी राष्ट्रीय भाषा हिन्दी में रक्षा एवं सामाजिक अध्ययनों की पत्र-पत्रिकाओं का अभाव होना खेद की बात है। क्या मंत्री महोदय यह बताएंग कि कितनी देर में यह अभाव दूर किया जाएगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीज: सभापति जी, मैंने कह दिया है कि जो बातें यहां पर कही गई हैं, उन पर विचार करके हम किसी निर्णय पर पहुंचेंगे।

SHRI C.P. THIRUNAVUKKARASU: Sir, I am very happy to know that Hindi language magazines and journals are being supplied in the field of defence and strategic studies. There are other regional languages like Tamil, Telugu, etc....(*Interruptions*)... I would like to know, specifically with regard to Tamil, whether magazines and journals are being supplied in this field or not ...(*Interruptions*)... It is very diffiucult for the Tamil and Telugu speaking people, who are working there, to understand Hindi. So, I would like to know whether regional language magazines are being supplied or not. The hon. Minister may please clarify this point.

SHRI GEORGE FERNANDES: The hon. Member's point is that defence-related matters should be brought to the knowledge of the public by the Government, in other words, by the Defence Ministry, in various languages. I mentioned earlier that as far as the question of literature in Hindi is concerned, on the basis of the points made by the hon. Members, I would have this proposition examined, and then we will come to a decision. I would like to make the same point to the hon. Member who suggested that magazines and journals in other languages on defence and strategic studies should be brought under consideration.

श्री संजय निरुपम: सभापति जी, इस प्रश्न के पीछे जो छुपा हुआ मूल भाव समझ में आ रहा है वह यह है कि यहां सवाल सिर्फ पत्र-पत्रिकाओं का नहीं है। हमारा जो रक्षा मंत्रालय है उसकी गतिविधियों से या उसकी नई उपलब्धियों से इस देश का आम आदमी वाकिफ नहीं हो पाता है क्योंकि सारा कामकाज और व्यवहार अंग्रेजी भाषा में होता है। इस देश का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो हिन्दी समझता है। इसके बाद क्षेत्रीय भाषाएं समझने वाले लोग हैं। इससे पहले जो सरकार थी, संयुक्त मोर्चा की, उस सरकार में जो रक्षा मंत्री थे, मेरे ख्याल से उन्होंने एक ऐसा सर्कुलर इश्यू किया था कि रक्षा मंत्रालय का सारा कामकाज हिन्दी में होगा। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या सचमुच में ऐसा कोई सर्कुलर इश्यू हुआ था? क्या इस सर्कुलर के हिसाब से अभी भी कोई काम हो रहा है?

दूसरी बात यह है कि हमें लोगों तक पहुंचना चाहिए। रक्षा मंत्रालय की नई उपलब्धियां क्या हैं? कौन से नए हथियार हमने खरीदे हैं? हमारे क्या-क्या परमाणु कार्यक्रम है? हमारे कार्यक्रम किस तरह से चल रहे हैं? अगर ये कार्यक्रम हम अंग्रेजी भाषा में प्रचारित करके लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। मैं पत्रिकाओं के बहाने यह जानना चाहूंगा कि क्या

रक्षा मंत्रालय की ऐसी कोई योजना या कार्यक्रम है कि हिन्दुस्तान का जो एक बड़ा वर्ग है, जो अंग्रेजी नहीं समझता, जो हिन्दी भाषा और क्षेत्रीय भाषाओं से जुड़ा हुआ वर्ग है, उन तक पहुंचने के लिए आपके पास कोई विशेष कार्यक्रम है जिससे रक्षा मंत्रालय के जो नियमित तौर के कार्यक्रम हैं, उनकी समझ हो सके?

श्री जार्ज फर्नान्डीज: सभापति जी, अंग्रेजी भाषा में ऐसी कोई पत्र-पत्रिका नहीं है जिसमें मंत्रालय की ओर से रक्षा मंत्रालय के कामकाज के बारे में प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। यह बात मैंने शुरू में ही बता दी है। यहां सेना का जिक्र भी हुआ है। वायु सेना है, थल सेना है और जो अन्य हमारी संस्थाएं हैं, उनकी तरफ से, उनके अपने कामकाज के बारे में, घर के भीतर जो कुछ पत्र-पत्रिकाएं बनाई जाती हैं, अगर वे बाहर कुछ सीमित लोगों तक पहुंच जाती हैं तो वहां कुछ अधिक प्रचार-प्रसार का काम उन पत्रिकाओं के जरिए नहीं होता है। इसलिए यह समझना कि रक्षा मंत्रालय की अंग्रेजी में पत्र-पत्रिकाएं हैं, हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में नहीं हैं, सही नहीं है। जहा तक पूर्व रक्षा मंत्री के सकुर्लर का सवाल है, जिसकी चर्चा माननीय सदस्य ने की, वह सर्कुलर इसके लिए था कि रक्षा मंत्रालय का कामकाज किस तरह से हो। रक्षा मंत्रालय के कामकाज में अंग्रेजी की जगह हिन्दी को प्राथमिकता दी जाए। वह सर्कुलर इस प्रकार का था। इस दिशा में जो कदम उठाए गए थे वे अभी भी जारी हैं।

श्रीमती सविता शारदा: सभापति जी, मेरा मंत्री जी से एक प्रश्न है कि हमारे यहां राजभाषा समिति बनाई जाती है। इसकी एक वर्ष में एक मीटिंग होती है। इसमें सभी बहुत जोर-शोर से कहते हैं कि हिन्दी भाषा का प्रचार-प्रसार होना चाहिए लेकिन उसके बाद पूरे साल कुछ नहीं होता है? मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या एक वर्ष की एक मीटिंग में ऐसा हो सकता है कि उसका प्रचार-प्रसार बढ़ाया जाए? मैं यह भी कहना चाहती हूं कि जितनी भी लाइब्रेरीज हैं, जो आपके रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं, उनमें कभी भी हिन्दी की पत्र-पत्रिकाएं नहीं देखी जाती हैं? अगर हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी है और हमें उसका प्रचार-प्रसार करना है तो मंत्री जी जितनी भी लाइब्रेरीज हैं तथा रक्षा संबंधी डिपार्टमेंट्स हैं, क्या इन सभी जगहों पर हिन्दी की पत्र-पत्रिकाएं लाइब्रेरीज में रखना चाहेंगे?

श्री जार्ज फर्नान्डीज: जहां कहीं हमारी लाइब्रेरी है, रक्षा मंत्रालय की अपनी एक लाइब्रेरी है, बाहर हर सेना विभाग की अपनी लाइब्रेरी है, इसके अलावा जहां-जहां भी हमारी यूनिट्स हैं उन स्थानों पर किताबें खरीदी जाती हैं। पत्र-पत्रिकाएं भी आती हैं। उनकी खरीद केवल अंग्रेजी भाषा की ही नहीं होती है। जिस इलाके में जिस भाषा की समझ होती है, वह तो है ही मगर हिन्दी को भी उतनी ही प्राथमिकता दी जाती है जितनी अंग्रेजी को दी जाती है।

श्री टी॰ एन॰ चतुर्वेदी: सभापति जी, जैसा मेरे सहयोगी ने कहा कि मूलभूत भावना यही है कि जो हमारी साधारण जनता है, विद्वानों के अतिरिक्त, उनके पास किस प्रकार से जानकारी जाए? जो हमारी रक्षा संबंधी समस्याएं हैं या उस संबंध में जो सरकार की नीतियां हैं, मंत्री जी ने यह सही कहा कि

मंत्रालय इस प्रकार की कोई पत्रिका नहीं निकालता है। लेकिन कई और संस्थान हैं जैसे एक इंस्टीट्यूट आफ डिफेंस एण्ड स्ट्रेटेजिक स्टडीज है, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट है, और भी एकाध संस्थान हैं, अब यूनिवर्सिटीज में भी कुछ जगह डिफेंस स्टडिज का विषय पढ़ाया जा रहा है, तो क्या मंत्री महोदय इस प्रकार का कोई प्रयास करेंगे या उनको प्रोत्साहन देंगे कि अच्छे-अच्छे आर्टिकिल्स जो इसमें आते हैं वे और जिनकी जानकारी एक सीधी सहज भाषा में साधारण लोगों को होनी चाहिए–उसमें सब राजभाषाएं शामिल हैं–इसके लिए क्या ऐसी कुछ व्यवस्था नहीं की जा सकती है कि वहां उनके लिए एक त्रैमासिका, अगर मंथली, मासिक, नहीं निकल सकती है, तो कम से कम कुछ त्रैमासिक पत्रिकाओं के छपने का प्रबंध किया जाए? क्योंकि पब्लिकेशंस डिवीजन के माध्यम से भी यह काम हो सकता है। वहां पर एक विकास संबंधी पत्रिका और विषयों में निकलती है। तो क्या इसकी महत्ता को देखते हुए जो डिफेंस का विषय है उसमें क्या इस प्रकार का कोई संयोजित प्रयास नहीं किया जा सकता है?

श्री जार्ज फर्नान्डीज: चेयरमैन सर, हम जरूर इस पर विचार करेंगे और निर्णय पर पहुंचेंगे।

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Sir, the translation should be done in all the National Languages, in all the regional languages. The Minister has said that it would be done only in Hindi. It is a very sensitive issue. The reply should have clearly mentioned it. ....(*Interruptions*)....

SHRI N. JOTHI: Mr. Chairman, Sir, here, the issue is that the major publications of the Defence Department should reach the common man. The common man does not read only Hindi. The common man reads Tamil, Malayalam, Kannada, Telugu, Marathi, Punjabi, and so on. A number of languages are spoken in our country. Our country is called India. ....(*Interruptions*).... Mr. Chaturvedi, please let me speak. Our country is called India, and not Hindustan. So, while making any attempt to publish Defence publications in Hindi, care should be taken to see that it is published simultaneously in all the regional languages. I am underlining the world '*simultaneously*'. It should be published in all the National Languages recognised by the Constitution. Sir, let it be published in all the languages. Hindi alone need not be given a special treatment.

AN HON. MEMBER: We all support you.

श्री टी॰ एन॰ चतुर्वेदी: मैंने कहा कि सब राष्ट्रीय भाषाएं मैंने हिन्दी को ही राजभाषा नहीं कहा, परन्तु मैंने कहा देश की सब राजभाषाएं।

SHRI N. JOTHI: The Defence Minister should support me. That is important.

SHRI GEORGE FERNANDES: Sir, I have already made the point that we would consider all these suggestions and then take a decision. In fact, I had said that it would be done in all the National Languages.

श्री राजीव शुक्ल: सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उन्होंने अपने जवाब में कहा है कि कैश अवार्ड स्कीम इसके लिए चालू की गयी है। क्या मंत्री जी बताएंगे कि अब तक कितने लोगों को नकद पुरस्कार इस योजना के तहत हिन्दी पब्लिकेशन के लिए दिया जा चुका है? दूसरा यह जो इनके इन-हाउस पब्लिकेशंस हैं इनका सर्कुलेशन क्या है और जो राजभाषा समिति की सिफारिशें हैं वे किस हद तक लागू हो रही हैं, किस स्तर तक?

श्री जार्ज फर्नान्डीज: सभापति जी, मैं अब सारी सूची तो यहां पढ़कर नहीं सुना सकूंगा क्योंकि लम्बी सूची है। किन-किन पत्रिकाओं को और कौन-कौन सी किताबें आदि हम लोगों ने ली हैं, कहां-कहां प्रोत्साहित करने के लिए जो पुरस्कार योजना है वह योजना दी गयी है, इसका दस्तावेज हम माननीय सदस्या को और सदन को दे देंगे।

श्री कलराज मिश्र: सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी है और सहयोगी भाषा के रूप में अंग्रेजी है। स्वभाविक रूप से सभी मंत्रालयों में जो भी प्रकाशन होता है दोनों भाषाओं में होता है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि मंत्रालय की तरफ से हिन्दी भाषा में कोई प्रकाशन नहीं है। राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी है, उसका सम्मान मंत्रालय के माध्यम से — जो सभी मंत्रालयों में अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में प्रकाशित करके होता है–करने की दृष्टि से क्या माननीय मंत्री जी तुरंत त्वरित कार्यवाही करने का प्रयत्न करेंगे?

श्री जार्ज फर्नान्डीज: सभापति जी, प्रश्न पत्र-पत्रिकाओं के बारे में था और मैंने यह कहा कि हमारे मंत्रालय की ओर से कोई भी पत्र-पत्रिका न अंग्रेजी में और न हिन्दी में निकाली जाती है, यह मैंने अपने उत्तर में पहले कहा है।

प्रो॰ रामबक्ष सिंह वर्मा: मान्यवर, राजभाषा अधिनियम के अनुसार भारत सरकार के सभी विभागों और भारत सरकार के नियंत्रण में जितने भी उपक्रम हैं उन सभी में पचास प्रतिशत व्यय हिन्दी भाषा की पुस्तकों पर होना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि रक्षा मंत्रालय में और रक्षा मंत्रालय से संबद्ध जितने भी अन्य अंग हैं उन सभी में क्या पचास प्रतिशत व्यय हिन्दी भाषा की पुस्तकों पर किया जा रहा है?

श्री जार्ज फर्नान्डीज: सभापति जी, इसके लिए मुझे नोटिस चाहिए।

SHRI EKANATH K. THAKUR: Sir, I am on a larger question. I feel that today..

MR. CHAIRMAN: Please put your question.

SHRI EKANATH K. THAKUR: Sir, I am putting my question, but before that I am giving a preamble.

Sir, today in various Defence services recruitments, youngmen are not coming forward in large numbers. One reason for this is that the post-Independence heroes are not properly projected to our young generation. The Defence Ministry knows that during the last three major wars, what kind of sacrifices have been made by the heroes of India. They know blow-by-blow account of their sacrifices. So, my question is: couldn't they publish the same documents which we could distribute in our schools and include them in our State syllabus languages? If people ought to know their sacrifices, then, our young children and young men must know these. Therefore, at least, the post-independence heroes must find a place in our text-books. If we have to tell them what happened during the past one hundred years, we ought to tell our present generation about the sacrifices made by our heroes in the post-Independence period. Therefore, their profiles should be included in the syllabus. Will the hon. Minister make available such documents where blow-by-blow account of the sacrifices made by the post-Independence youths can be highlighted?

श्री जार्ज फर्नान्डीज: सभापति जी, भारत के सामरिक इतिहास के बारे में और विशेषकर आजादी के बाद के सामरिक इतिहास के बारे में किताबें लिखी गई हैं और हमारे देश में अनेक किताबें हैं तथा द्विभाषाओं में वे किताबें मिलेंगी। मंत्रालय की ओर से प्रयास अभी जारी है कि आजादी का बाद का एक अधिकृत सामरिक इतिहास लिखा जाए और उस दिशा में जो पहल हुई है वह जब समाप्ति की तरफ जाएगी तो निश्चित तौर पर वह इतिहास न केवल सामान्यजन को, बल्कि स्कूलों-कालेजों में भी पढ़ने व पढ़ाने के लिए हासिल हो सकेगा।

SHRI KULDIP NAYYAR: Sir, whether a publication is in Hindi or in English, the basic point is self-sufficiency of the publication. I would like to know whether any effort is being made whereby the publications, which are coming out from the Defence Ministry, are self-sufficient.

Part (b) of my question is: May I know whether these publications are also open to foreign investors, because you have opened 26 per cent share for them? Can they also invest in those publications?

श्री जार्ज फर्नान्डीज: सभापति जी, हमारे रक्षा मंत्रालय में विदेशी पत्रकारिता के लिए कोई स्थान होगा ऐसा मुझे नहीं लगता है और सैल्फ-स्फीशिएंट करके माननीय सदस्य ने जो कहा है वह मै समझ नहीं पाया कि सैल्फ-स्फीशिएंट किस मायने में यानी प्रकाशित करके उसको लोगों तक पहुंचाने की दृष्टि से या उस पर जो खर्च होता है, उस खर्च की दृष्टि से, यह स्पष्ट नहीं हुआ।

श्री जयन्ती लाल बरोट: सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह हर जवाब में ऐसा कह देते हैं कि विचार करेंगे, तो क्या उसकी कोई मर्यादा होगी या फिर यही जवाब होगा? दूसरी बात मैं जानना चाहता हूं कि हमारे टी॰ वी॰ के जो चैनल होते हैं उनके माध्यम से हम लोगों को जानकारी देने के लिए सोच रहे हैं या नहीं?

श्री जार्ज फर्नान्डीज: सभापति जी, टी॰ वी॰ के माध्यम से तो रक्षा मंत्रालय की तरफ से जानकारी नहीं दी जाएगी। रक्षा मंत्रालय के कामकाज पर टी॰ वी॰ चैनल जो भी बात कहना चाहेगा, या उस पर जो चर्चाएं होंगी, वह तो होती रहेगी। अब जहां तक हम ने कब कोई बात कही या यहां जो भी बातें छेड़ी गयी, उन पर विचार कर हम एक निर्णय पर पहुंचेंगे। इस बारे में समय तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हमारा प्रयास होगा और शीघ्र ही इस बारे में विचार कर के हम एक निर्णय पर पहुंच जाएंगे।

श्री सभापति: प्रश्न संख्या 145, श्री संतोष बागड़ोदिया।

श्री संतोष बागड़ोदिया: सर, मुझे आप का प्रोटेक्शन चाहिए क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां देश में इन्होंने पैदा कर रखी हैं **(व्यवधान)**

श्री सभापति: आप सवाल पूछिए।

श्री संतोष बागड़ोदिया: उस में सवाल पूछने पर लगता है कि यहां तहलका मच जाएगा और पूरे देश में तहलका मच जायेगा। ....**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: आप सवाल पूछिए।

श्री संतोष बागड़ोदिया: इसलिए मैं माफी चाहता हूं। अगर प्रोटेक्शन देने की गांरटी करें, अन्यथा मैं सवाल नहीं पुछूंगा। धन्यवाद।

*145. WITHDRAWN

Water Conservation and Wasteland Development in Karnataka

*146. SHRI H.K. JAVARE GOWDA: Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the details of amount sanctioned and released by the Central Government to Karnataka for the past three years under Water Conservation and Wasteland Development Programmes;

(b) whether Karnataka has fully utilised the amount earmarked by the Centre; and

(c) if so, the details of the progress of the above programmes in the State?